through the D.G.S.&D. I do, not manufacture these bulk drugs. Wherever there is a shortage, on the spot, if they are required, some authorities are given to the hospitals. It is the hospital committees which purchase these drugs when they are required urgently.

MR. CHAIRMAN: Now, Matters under 377. Shri Bhookhabhai.

13.08 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR SURVEY FOR EXPLORATION OF MINIRALS IN DUNGARPUR AND BANSWARA DISTRICTS OF RAJASTHAN.

श्री भोखा भाई (बांसवाड़ा): महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू।

राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है। उसमें भी कुछ एक इलाके जो इसके दक्षिण में गुजरात के साथ हैं, विशेषकर डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले और भी अधिक पिछड़े हुए हैं। ये प्रदेश मुख्यत: जन-जाति के लोगों के हैं। हमारी सरकार की यह नीति रही है कि पिछड़े हुए प्रदेशों का विशेष रूप से विकास किया जाए। इसकी आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है यदि ये प्रदेश विशेषकर गरीब जन-जाति, पिछड़े हुए लोगों के हों अभी हाल ही में भी भारत सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति में इस बात का एलान किया है।

राजस्थान के इन जिलों में विशेषकर डूंगरपुर के इलाकों में कई खनिज भरे पड़े हैं। अभी तक इन खनिज पदार्थों का पूरा न तो सरकार को पता चला है और न ही इस प्रदेश का कोई प्रभावित सर्वे हुआ है। अत: मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि इन इलाकों को खनिज की खोज करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करना चाहिये। प्रदेश की सरकार भी इस ओर कार्य कर रही है। पर यह यथेष्ठ नहीं है क्योंकि प्रदेश सरकार के पास न तो पूरी धन की व्यवस्था है और न ही अन्य आवश्यक साधन। इस दिशा में अगर आवश्यक समझा जाए तो विदेशी सहयोग भी लिया जा सकता है। एक बार खनिजों का सर्वे होने के बाद उनका वहीं पर कारखानों द्वारा उपयोग यहां के मूल निवासियों की काया पलट कर देगा। यही नहीं इन खनिजों में बहुत से खनिज तो ऐसे भी हैं जिससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी।

अत: मेरा स्टील एवं माइंस मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि वे इस दिशा में शीघ्र कार्यक्रम शुरू करें एवं सदन को एक वक्तव्य दें।

(ii) NEED FOR FINANCIAL ASSISTANCE FROM BANKS ETC. FOR DEVELOPMENT OF SMALL SCALE UNITS IN KHERI LAKHIMPUR AREA OF U.P.

श्रीमती उषा वर्मा (खेरी): सभापति जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके विशेषकर मेरे संसद क्षेत्र खीरी-लखीमपुर के इलाके भयंकर प्रकृति-विपदा से ग्रस्त हैं। एक तो यह इलाके वैसे ही पिछड़े हुए हैं उसपर पिछले कुछ वर्षों से सूखा एवं अभी हाल ही में पड़ी ओला वृष्टि ने तो गरीब किसानों की कमर ही तोड़ दी है। इस बारे में राज्य सरकार के द्वारा की जा रही सहायता काफी नहीं होगी क्योंकि उस के पास सीमित साधन हैं। जब तक केन्द्रीय सरकार अपने विशेष कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ विशेष उपाय नहीं करती है इस इलाके के लोगों का निर्वाह बड़ा मुश्किल होता जा रहा है।

यहां कुछ एक छोटे-मोटे उद्योग धन्धे भी और पनप सकते हैं। इस में विशेष योगदान राष्ट्रीयकृत बैंकों का

[श्रीमती उषा वर्मा]

हो सकता है। क्योंकि कच्चा माल उपलब्ध होते हुये भी लोग धन के अभाव में अपने छोटे-मोटे धंधे स्थापित करने में असमर्थ हैं। इस लिये मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि यहां की जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बैंकों से उनको ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक मात्रा में लोगों को छोटे-मोटे धंधों के लिए विशेष धन की व्यवस्था कराये।

इस प्रदेश में गन्ने की मुख्य खेती होती है और सरकार सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों में चीनी-मिलों को लगा सकती है। इस ओर विशेष धन वित्त निगमों से प्राप्त हो सकेता है। सरकार को इन निगमों से विशेष आग्रह करना चाहिये कि वे इन क्षेत्रों में धन-साधन उपलब्ध कराने से न कतरायें। ऐसा इस प्रदेश की जनता के विकास के लिये नितान्त आवश्यक है।

(iii) SUPPLY OF CEMENT AND COAL FOR RAJASTHAN CANAL PROJECT

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान नहर परियोजना के लिये कोयला और सीमेंट की लगातार चार वर्षों से पर्याप्त व्यवस्था नहीं करने के कारण प्रति वर्ष स्वीकृत राशि व्यय नहीं की जा रही है। जिस के कारण राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और नहर के निर्माण में विलम्ब होता जा रहा है। जिस से नहर के निर्माण में भी बढ़ती हुई मंहगाई के कारण अधिक व्यय होता है और रेगिस्तान का क्षेत्र सिंचित होने से वंचित रहता है। सन 1981–82 में परियोजना के तहत 52 किलोमीटर लाइनिंग कार्य का प्रस्ताव था, किन्तु कोयले और सीमेंट की कमी के चलते जनवरी, 1982 तक मात्र 9.68 कि० मी० में ही लाइनिंग कार्य हो पाया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित लक्ष्य को संशोधित कर इस वर्ष 30 किलोमीटर में ही लाइनिंग का कार्य कराने का निश्चय किया गया है। जो लक्ष्य भी सीमेंट व कोयले की कमी के कारण प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

परियोजना को वर्ष सन् 1981–82 में 79 हजार मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता थी जब कि जनवरी 1982 तक मात्र 38 हजार 452 मीट्रिक टन कोयला ही सुलभ हो सका। इसी प्रकार वर्ष सन् 1981–82 में सीमेंट की कुल 80 हजार मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले मार्च, 1982 तक 31 हजार 445 मीट्रिक टन सीमेंट मिल पाई। कोयले व सीमेंट की कमी के कारण नहर की प्रगति धीमी होने के बारे में केन्द्र सरकार का कई बार ध्यान आकर्षित किया गया है परन्तु केन्द्र सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है।

अतः केन्द्र सरकार का इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जा कर मांग है कि प्रति वर्ष पर्याप्त आवश्यक मात्रा में कोयला व सीमेंट की व्यवस्था की जावे ताकि लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति हो सके और राजस्थान नहर परियोजना का कार्य छटी पंचवर्षीय योजना काल में सम्पूर्ण किया जा सके।

(iv) DEMANDS FOR IMPROVEMENT OF RAILWAY FACILITIES ON PANSKURA—HALDIA SECTION OF SOUTH EASTERN RAILWAYS.

SHRI SATYAGOPAL MISRA (Tamluk): The people residing around the Panskura-Haldia section of the South Eastern Railways are suffering from the inadequate Railway facilities and demanding immediate improvement of the Railway system of the line.